

सड़क, रेल और हवाई यात्रा में विकास व सुरक्षा की खाई पाटे सरकार

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी, तब देश का ध्यान केवल नए एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनों और



हवाई अड्डों के विस्तार पर नहीं बल्कि इन दांचागत सुविधाओं की

सुरक्षा पर भी होना चाहिए। बीते वर्षों में सड़क, रेलवे और विमानन सेक्टर में निवेश अभूतपूर्व रहा है। लेकिन इसके समानांतर यात्रा को सुरक्षित बनाने की रफ्तार उतनी तेज नहीं दिखती। पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतें, रेल हादसों की आशंका और विमानन निगरानी तंत्र पर उठते सवाल यह संकेत देते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अब सुरक्षा सुधार के बिना अधूरा है। बजट 2026-27 सरकार के लिए यह अवसर है कि वह विकास और सुरक्षा के बीच की इस खाई को पाटे और स्मार्ट निवेश व नीतिगत बदलाव करे ताकि हम एक सुरक्षित भारत की ओर बढ़ें।

क्यों जरूरी है सुरक्षा को प्राथमिकता देना

सड़क : 2023 में सड़कों पर 1.72 लाख मौतें हुईं, जो रोजाना औसतन 470 मौतों के बराबर है। उस वर्ष 4.8 लाख दुर्घटनाएं हुईं। आंकड़े बताते हैं कि दुर्घटना की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ी है लेकिन मौतों की संख्या 80 प्रतिशत बढ़ी है। यानी दुर्घटनाएं ज्यादा घातक हो रही हैं। जैसे मुख्य कारण ओवरस्पीडिंग (71 प्रतिशत मौतें), शराब पीकर ड्राइविंग, गलत दिशा में चलना और हेलमेट/सीट बेल्ट न पहनना है। सड़कों की गुणवत्ता भी एक प्रमुख कारण है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारों के स्तर पर इन मौतों को किस तरह से रोका जा सकता है? जानकारों का कहना है कि हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की

भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्र नियमों, नीतियों व कानूनों के जरिए एक बानगी पेश कर सकता है। सभी राज्यों को सुरक्षित यातायात को परीयता देने का दबाव बना सकता है। केंद्र की पहल पर पूरे देश में स्मार्ट सिग्नलिंग या एआइ आधारित ट्रैफिक निगरानी प्रणाली को अपनाने की नीति लागू की जा सकती है। हेलमेट और सीटबेल्ट अनुपालन की तकनीकी निगरानी को भी मजबूत किया जा सकता है। इमरजेंसी मेडिकल रिसपांस नेटवर्क के राष्ट्रीय क्रियान्वयन को भी जरूरी माना जा रहा है ताकि बचाव टीम को देश के कोने-कोने में दुर्घटना-स्थल तक जल्दी पहुंचने की व्यवस्था हो।

रेलवे : आंकड़ों में भारतीय रेलवे में दुर्घटना की संख्या कम हुई है। 1960 के दशक में सालाना 1,390 दुर्घटनाएं



हुई थीं, जिनकी संख्या घटकर अब करीब 80 पर सिमट गई है। लेकिन वर्ष 2023-24 में 40 गंभीर हादसे हुए। सबसे बड़ा कारण बोरियों का डिरेलमेंट यानी पटरों से उतरना है। 55 प्रतिशत से ज्यादा दुर्घटनाओं के लिए मानवीय गलतियों को जिम्मेदार माना गया।

1.72 लाख मौतें हुई थी कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान पूरे देश में सड़क हादसों के कारण, उस वर्ष 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं

71% मौतें ओवरस्पीडिंग के कारण होती हैं सड़क हादसों में शराब पीकर या गलत साइड ड्राइविंग और हेलमेट न पहनना भी प्रमुख कारण



विमानन : अगर एविएशन की बात की जाए तो में 2025 का एअर इंडिया विमान एआइ-171 दुर्घटना (260 मौतें)



जैसे हादसे हुए, जिसने जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। दिसंबर, 2025 में भारतीय एविएशन सेक्टर में तकरीबन 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो की एक साथ सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से जो हालात पैदा हुए, उसने नियमन संबंधी कमजोरियों को बाहर ला दिया है।

कौन-कौन से कदम उठाए जाने चाहिए

- अगले बजट में सभी प्रमुख मार्गों पर कवच और सीबीटीसी जैसे उन्नत ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के विस्तृत विस्तार की घोषणा कर यात्रा को सुरक्षा बनाने का भरपूर दिलाया जाए
- कवच के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा होनी चाहिए
- रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ड्रोन व एआइ के इस्तेमाल को लेकर

- भी महत्वाकांक्षी कदम उठाए जाएं
- डीजीसीए को अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करने की घोषणा करके इस सेक्टर में ज्यादा नीतिगत स्पष्टता लाई जाए
- भारत को विमानन क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने के लिए विमान रखरखाव व मरम्मत नेटवर्क को लेकर अलग से विशेष कोष स्थापित करने की जरूरत

दूसरे देशों से सीखने की जरूरत

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनमी बनने के साथ ही सरकार की मंशा साफ है कि अगले वाले वर्षों में अभी सड़क, रेलवे व हवाई नेटवर्क पर भारी भरकम निवेश हो। यहां सरकार चाहे तो चीन व जापान से काफी कुछ सीख सकती है, जहां सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार टेक्नोलॉजी आधारित समाधान पर काम किया जा रहा है। चीन की हाई-स्पीड रेल (60,809 किमी नेटवर्क) में मौतें बहुत कम होती हैं क्योंकि ग्रेड सेपरेशन, अग्रिम सिग्नलिंग और नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। भारत में जहां दो प्रतिशत सड़कें 36 प्रतिशत

मौतों के लिए जिम्मेदार है, वहीं चीन ने एक्सप्रेसवे नेटवर्क का जाल बिछाने के बावजूद दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया है। जापान में भूकंप अलर्ट वार्निंग सिस्टम ट्रेनों को पहले रोक देता है। यूरोप और अमेरिका में पाजिटिव ट्रेन कंट्रोल (पीटीसी) से दुर्घटनाओं में 80 प्रतिशत कमी की गई है। यूरोप में यात्री प्रति किमी पर मौतें भारत से 10 गुना कम हैं, क्योंकि सख्त कानून प्रवर्तन है। इन सभी देशों में केंद्रीय कानून के तहत सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन होता है। इनसे सीखते हुए 2026-27 बजट में सरकार को सुरक्षा पर केंद्रित करना चाहिए।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

DAINIK JAGRAN

JAIPUR

17 JANUARY 2026

जयपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित

नवज्योति, जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार चौथे दिन उड़ानों के संचालन पर असर देखने को मिला। इंडिगो एयरलाइंस की जयपुर से चंडीगढ़ फ्लाइट शुरुवार को भी रद्द रही। यह फ्लाइट रोज सुबह 5.50 बजे जयपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है, लेकिन लगातार चौथे दिन रद्द होने से सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा स्पाइसजेट की इंटरनेशनल फ्लाइट भी देरी से संचालित हुई। जयपुर से सुबह 9.40 बजे दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट शुरुवार को करीब 50 मिनट की देरी से सुबह 10.30 बजे रवाना हुई। वहीं इंडिगो की जयपुर से मुंबई फ्लाइट भी निर्धारित समय से करीब तीन घंटे लेट रही। यह फ्लाइट सुबह 10.55 बजे के बजाय दोपहर 1.55 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। हैदराबाद-चंडीगढ़ फ्लाइट जयपुर डायवर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खराब मौसम और घने कोहरे के कारण इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट शुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा।

यह फ्लाइट हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही थी, लेकिन चंडीगढ़ में दृश्यता बेहद कम होने के चलते विमान की सुरक्षित लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। एटीसी ने विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं देते हुए जयपुर डायवर्ट किया, जहां विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड कराया।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

NAVBHARAT TIMES

DELHI

18 JANUARY 2026

दिल्ली एयरपोर्ट में 4 महीने तक एक रनवे होगा बंद

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दिल्ली एयरपोर्ट अपना एक रनवे लंबे समय के लिए बंद करने जा रहा है। अभी इसकी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन फरवरी मिड से लेकर यह चार महीने तक बंद रहेगा। दरअसल, इंफ्रस्ट्रक्चर अपग्रेड करने की वजह से यह बंद रहेगा। रनवे 11R/29L में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।

देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आईजीआईए) में इस खलल की वजह से यात्रियों को दिक्कत बढ़



सकती है। इन दिनों कोहरे की वजह से उड़ानों के संचालन में दिक्कत हो रही है। डीजीटीसी ने 15 फरवरी तक यही स्थिति रहने का अनुमान बताया है। इसके फौरन बाद एक रनवे बंद को जाने की वजह से दिक्कतें बनी रहने की आशंका है।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

TIMES OF INDIA

DELHI

18 JANUARY 2026

Airport wheelchair abuse shows our love for gaming the system

THE UNDERAGE OPTIMIST



CHETAN BHAGAT

Did you know that many Indians have a unique medical condition? When it comes to catching flights at airports, particularly international ones, they are suddenly unable to walk. A CISF survey in 2024 suggested that approximately 12% of travellers from Indian airports taking international flights book wheelchairs.

Sure, there are people with genuine mobility issues and need wheelchair support. However, it is hard to believe that one in eight Indians can't walk.

Air India reportedly gets more than 100,000 wheelchair requests every month. On some long-haul routes like India to New York or Chicago, some 30% of travellers book wheelchair assistance.

If that figure is accurate, that's 80-100 wheelchair requests per flight!

Airlines and airport authorities have requested people multiple times not to abuse this free service meant for people with genuine disabilities. But Indian travellers not only misuse it at home but also at international airports. The damage to India's reputation is clear from social media posts.

Far from feeling ashamed, many Indians see this as a clever hack to navigate lengthy, complicated and crowded airports. An able-bodied human pushes your wheelchair, bypasses queues, helps you clear security and immigration and then drops you off at the lounge and boarding gate, even as you watch reels and videos on your phone. Wow, you really did figure out a way to game the system, didn't you?

In fact, it is this constant need to 'game the system' that is at the heart of such behaviour.

Airports are stressful everywhere, but in India they can be even more so, often due to poor design, archaic procedures and old equipment. We don't have enough sub-terminals for drop-offs, so you walk kilometres to your gate. Our X-ray machines are so ancient that you have to remove every coin, wire, key, charger, battery, and possibly your soul from your bag. You unpack, repack, and unpack again as if it's a sport. Then come the rubber stamps, the multiple boarding pass checks and the same question asked five times by five different people.

At some point, you think: Why walk when I can roll? Wheelchair assistance offers a clear, immediate benefit: priority movement through security, immigration, and boarding. For a traveller anxious about missing a flight

or simply unwilling to endure discomfort, the wheelchair becomes a shortcut in an inefficient system.

Behavioural psychology calls this incentive-driven rationalisation. When the cost of cheating is low, the benefit high and enforcement weak, even otherwise 'moral' individuals may justify rule-bending. Some simply convince themselves that they are "temporarily unwell," "deserving," or merely "using what's available".

A deeper explanation lies in what psychologists describe as a scarcity mindset. Indian society, shaped by centuries of resource constraint, competition, and population pressure, often fosters the belief that opportunities are limited and must be seized aggressively. When systems feel unfair or overburdened, people are more likely to adopt zero-sum thinking: if I don't take advantage, someone else will. In such a mindset, abusing a wheelchair is not viewed as stealing from a disabled person, but as "beating the system".



PAYING A PRICE: The real victims are those with disabilities who are viewed with suspicion by airline staff

In fact, we try to game or beat the system in other areas as well. Queue jumping, traffic violations such as ignoring signals or lanes, misuse of quota certificates, littering and vandalising public property such as trains is all part of behaviour we commonly see in India. In each case, the pattern is similar: weak enforcement, low shame, high personal gain.

This isn't uniquely Indian behaviour. Any overcrowded society with low trust and weak institutions demonstrates such behaviour. India's massive scale just amplifies it and makes it visible, now even on the global stage.

The real victims of the wheelchair scam are those with disabilities. They will either not get wheelchairs or be seen with suspicion by airline staff who lose empathy after witnessing repeated misuse of the facility.

As we modernise our infrastructure, there is a corresponding need to improve civic education as well. Breaking rules shouldn't be cool. Following them well should be. As that cultural shift will take a while, we should, meanwhile, have heavy penalties for misuse of wheelchairs. Airports also need to simplify their procedures and modernise their equipment, some of which are dated and far behind other international airports. Queues have to move fast. There can be more golf cart shuttles for gates located far away.

And for those who frequently book wheelchairs even though they don't need them, please stop. Leave this facility for people who genuinely need it. Be grateful to God that your legs still work. Use them. Walk. Notch up your daily step count. It's good for you anyway. ■

Corporate Communications Directorate

ASIAN AGE

DELHI

18 JANUARY 2026

DGCA fines Indigo ₹22.2cr over '25 flight chaos

Airline has been asked to provide ₹50cr bank guarantee ■ CEO among top mgmt warned

VINEETA PANDEY
NEW DELHI, JAN 17

The Director General of Civil Aviation (DGCA) has slapped a hefty penalty of ₹22.20 crore on IndiGo for the flight cancellations that stranded nearly three lakh passengers last December. The penalty includes charges for non-compliance with new flight duty time limitation (FDTL) rules, which the airline had requested extra time to implement until February 10, 2026. In addition, IndiGo has been ordered to pledge a ₹50 crore bank guarantee to the DGCA to ensure long-term systemic compliance. Top management,

including CEO Pieter Elbers, received warnings against any repeat of such operational failures. Lakhs of passengers faced massive inconvenience due to abrupt flight cancellations and delays by IndiGo between December 3 to 5, 2025. A total of 2,507 flights were cancelled and 1,852 were delayed, leaving passengers stranded at various airports.

The DGCA had in December constituted a four-member committee to carry out a comprehensive review and assessment of the circumstances leading to the operational disruptions of IndiGo. During the probe, the committee took statements of the

▶ **TO PLUG** problems at its own end and correct systems within, the DGCA has started an internal inquiry to identify and implement improvements within its own systems

stakeholders and thoroughly studied the network planning, rostering and software being deployed by IndiGo.

The inquiry committee found that the primary causes for the disruption were over-optimisation of operations, inadequate regulatory preparedness along with deficiencies in system software support and shortcomings in man-

agement structure and operational control on the part of IndiGo.

The committee observed that the airline's management failed to adequately identify planning deficiencies, maintain sufficient operational buffers, and effectively implement the revised FDTL provisions. These lapses resulted in widespread flight delays and large-scale cancellations, causing inconvenience to passengers.

"The inquiry further noted an overriding focus on maximising utilisation of crew, aircraft, and network resources, which significantly reduced roster buffer margins. Crew rosters were designed to max-

imise duty periods, with increased reliance on dead-heading, tail swaps, extended duty patterns, and minimal recovery margins. This approach compromised roster integrity and adversely impacted operational resilience," the DGCA officials said.

The DGCA has also cautioned the CEO for inadequate overall oversight of flight operations and crisis management. Warning has been issued to the accountable manager (COO) for failure to assess the impact of Winter Schedule 2025 and the revised FDTL CAR leading to widespread disruptions.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

AMAR UJALA

DELHI

18 JANUARY 2026

हैदराबाद में 28 से एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया

मुंबई। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 जनवरी से हैदराबाद के बेगमपेट हवाईअड्डे पर होगा। 31 जनवरी तक चलने वाले शो की थीम भारतीय विमानन : भविष्य की राह रखा गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू करेंगे। शो में विमानन मूल्य शृंखला के प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के भाग लेने की उम्मीद है। व्यूरो



Corporate Communications Directorate

BUSINESS LINE

DELHI

18 JANUARY 2026

DGCA slaps ₹22 cr fine on IndiGo over disruptions

Rohit Vaid
New Delhi

India's aviation safety regulator, Directorate General of Civil Aviation (DGCA), has imposed financial penalties amounting to ₹22.20 crore on IndiGo following an inquiry into large-scale flight disruptions reported last month. Accordingly, of the total penalty, ₹1.80 crore has been imposed as one-time systemic fines for multiple instances of regulatory non-compliance.

Besides, ₹20.40 crore has been levied for continued non-compliance with the revised flight duty time limitation (FDTL) norms over 68 days — from December 5, 2025 to February 10, 2026. Also, DGCA has directed IndiGo to pledge a ₹50-crore bank guarantee under the IndiGo Systemic Reform Assurance Scheme (ISRAS).

Per the regulator, the

phased release of the bank guarantee will be linked to DGCA-verified implementation of corrective measures.

PHASED FUND RELEASE

Under the ISRAS framework, ₹10 crore of the bank guarantee is linked to leadership and governance reforms to be certified within three months. A tranche of ₹15 crore is tied to manpower planning, rostering and fatigue-risk management over six months. Another ₹15 crore is linked to digital systems upgrades and operational safeguards within nine months. The remaining ₹10 crore is associated with sustained board-level oversight over 9-15 months. DGCA has also issued cautions to several senior officials of InterGlobe Aviation. These include a caution to the CEO Pieter Elbers for inadequate oversight of flight operations and crisis management.

Furthermore, a warning

was issued to the Accountable Manager and COO for failure to assess the impact of the Winter Schedule 2025 and the revised FDTL provisions. Meanwhile, the Senior Vice-President, Operations Control Centre, was warned and directed to be relieved of current responsibilities. Other senior officials involved in flight operations and crew resource planning were also warned.

The enforcement action follows an inquiry conducted by a four-member committee constituted by the DGCA which was initiated after IndiGo reported the cancellation of 2,507 flights and delays to 1,852 flights between December 3 and 5, 2025, affecting over three lakh passengers across the country.

KEY CAUSES

According to the committee, the primary causes of the disruptions were over-optimisa-

tion of operations, inadequate regulatory preparedness, deficiencies in system software, and shortcomings in management oversight and operational control. The committee observed that the airline failed to maintain adequate operational buffers and did not effectively implement the revised FDTL provisions, leading to widespread delays and cancellations.

Per the inquiry, crew rosters were designed to maximise utilisation of aircraft and crew, including greater reliance on dead-heading, tail swaps, extended duty patterns, and minimal recovery margins, which hit operational resilience.

Separately, the DGCA has initiated an internal inquiry to identify and implement systemic improvements in regulatory processes. In a message, IndiGo's Chairman and the board said corrective measures will be taken.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

DAINIK BHASKAR

DELHI

18 JANUARY 2026

दिल्ली में सांसद के साथ बैठक, सैद्धांतिक मंजूरी मिली एअर इंडिया भोपाल से कोलकाता, चेन्नई की उड़ान शुरू कर सकता है



दिल्ली में एअर इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक करते सांसद आलोक शर्मा।

भोपाल | भोपाल से हवाई संपर्क को सशक्त बनाने की दिशा में सांसद आलोक शर्मा ने दिल्ली में एअर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक आलोक सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सांसद शर्मा ने बताया कि भोपाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 24x7 संचालन के लिए अधिसूचित है और आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त है। राजधानी होने के कारण भोपाल से हवाई यात्रा की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने चेन्नई, पटना, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी घरेलू उड़ानों के साथ दुबई को अंतरराष्ट्रीय गंतव्य के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव रखा।

उड़ानें रद्द व विलंब पर इंडिगो पर 22.20 करोड़ का जुर्माना

डीजीसीए की कार्रवाई, 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर दिसंबर, 2025 के शुरुआत में उसकी हजारों उड़ानों के रद्द होने और उनमें विलंब होने के मामले में 22.20 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एकमुश्त दंड और निरंतर गैर-अनुपालन के लिए लगाई गई दैनिक पेनाल्टी का जोड़ है। साथ ही, एयरलाइन को 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का भी आदेश दिया है ताकि दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित हो सकें। इंडिगो को आपरेशनल खामियों के चलते तीन लाख से अधिक यात्री विभिन्न एयरपोर्टों पर फंस गए थे, इससे उन्हें भारी परेशानी हुई थी।

पिछले महीने, एयरलाइन को नए उड़ान ड्यूटी टाइम लिमिटेशन मानदंडों के अनुपालन के लिए 10 फरवरी तक छूट दी गई थी। एक असामान्य कदम के तहत, डीजीसीए ने पांच दिसंबर, 2025 से 10 फरवरी, 2026 तक 68 दिनों को अवधि के लिए अनुपालन न करने पर एयरलाइन पर कुल



- दिसंबर में इंडिगो की 2,507 उड़ानें रद्द हुई थी, 1,852 उड़ानों में देरी हुई
- तीन लाख यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी, हवाई अड्डों पर फंसे रहे थे

20.40 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह राशि प्रत्येक दिन के लिए 30 लाख रुपये के जुर्माने के बराबर है। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन के लिए एकमुश्त दंड 1.80 करोड़ रुपये लगाया गया है।

यह जुर्माना अब तक किसी भी एयरलाइन पर उड़ान बाधित करने के लिए नियामक द्वारा लगाए गए सबसे बड़े जुर्माने में से एक है, अन्य नियामक कार्रवाइयां भी अभूतपूर्व हैं। पिछले माह परिचालन आघातों के बाद डीजीसीए ने इंडिगो की शीतकालीन उड़ानों को संख्या 10% तक कम कर दी थी।

तीन से पांच दिसंबर, 2025 के

डीजीसीए के आदेश का पालन होगा: इंडिगो

इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि वह नियामक के आदेशों का पालन करेगी। एयरलाइन प्रवक्ता ने कहा - 'इंडिगो प्रबंधन डीजीसीए के आदेशों का संज्ञान लेने के लिए प्रतिबद्ध है। गड़बड़ी के बाद से हमारी आंतरिक प्रणालियों की समीक्षा की जा रही है ताकि एयरलाइन अपने परिचालन रिकार्ड को और मजबूत बना सके।'

दौरान इंडिगो को 2,507 उड़ानें रद्द हुई थीं और 1,852 उड़ानों में देरी हुई थी। इस संकट के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर डीजीसीए ने एक चार सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने विस्तृत जांच के बाद तीन मुख्य कारणों की तरफ ध्यान दिलाया है। इसमें सबसे प्रमुख है क्षमता का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हुए परिचालन। इसके अलावा अपवांशित नियामक तैयारियां, साफ्टवेयर की कमियां तथा प्रबंधन संरचना व परिचालन निबंधन में खामियों को अन्य कारण बताया गया है।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

DAINIK JAGRAN

DELHI

18 JANUARY 2026

इंडिगो के सीईओ एल्वर्स को चेतावनी, ओसीसी को पद से हटाया गया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बताया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। सीईओ पीटर एल्वर्स को अपर्याप्त निगरानी के लिए चेतावनी दी गई है। सीओओ को विंटर शेड्यूल को लेकर सही अनुमान नहीं लगाने को लेकर चेतावनी दी गई है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ओसीसी) को वर्तमान जिम्मेदारी से हटाने और किसी भी जिम्मेदारी वाले पद पर न लगाने का निर्देश दिया गया है। डिप्टी हेड-फ्लाइट आपरेशंस, एवीपी-क्रू रिसोर्स प्लानिंग और डायरेक्टर-फ्लाइट आपरेशंस को भी विभिन्न स्तरों पर लापरवाही के लिए वार्निंग जारी की गई। इंडिगो ने अपने पायलटों और क्रू-मेंबर्स के काम के शेड्यूल को इतना टाइट बना दिया था कि थोड़ी समस्या आने पर सब बिगड़ जाता था। विंटर शेड्यूल 2025 व संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के प्रभाव का आकलन करने में विफलता भी एक बड़ा कारण रहा।

Corporate Communications Directorate

RS DAINIK JAGRAN

DELHI

18 JANUARY 2026

उड़ानें रद्द और विलंब करने पर इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना

डीजीसीए की सख्त कार्रवाई, 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का भी दिया आदेश

जागरण न्यूसे, नई दिल्ली

विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर दिसंबर, 2025 की शुरुआत में उसकी हजारों उड़ानें रद्द और विलंबित होने के मामले में 22.20 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एकमुश्त दंड और निरंतर गैर-अनुपालन के लिए लगाई गई दैनिक पेनाल्टी का जोड़ है। साथ ही, एयरलाइन को 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का भी आदेश दिया है ताकि वैधकालिक सुधार सुनिश्चित हो सके। उस प्रकरण से दुनियाभर में भारत के एविएशन सेक्टर की बड़नामी हुई थी। इंडिगो की आपरेशनल खमियों के चलते तीन लाख से अधिक यात्रियों को भारी परेशानों का सामना करना पड़ा था। यंत्री कई-कई घंटे एयरपोर्टों पर फंसे रहे थे। हवाई अड्डों पर अफरातफरी का माहौल रहा था।

पिछले महीने, एयरलाइन को नए उड़ान ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) मानदंडों के अनुपालन के लिए 10 फरवरी

तीन से पांच दिसंबर के बीच इंडिगो की 2,507 उड़ानें रद्द हुई थीं और 1,852 उड़ानों में देरी



प्रतीकात्मक

तक छूट दी गई थी। एक असामान्य कदम के तहत, डीजीसीए ने पांच दिसंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक 68 दिनों की अवधि के लिए अनुपालन न करने पर एयरलाइन पर कुल 20.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि प्रत्येक दिन के लिए 30 लाख रुपये के जुर्माने के बराबर है। इसके अलावा विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए एकमुश्त दंड 1.80 करोड़ रुपये लगाया गया है। इस तरह डीजीसीए ने इंडिगो पर कुल 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह जुर्माना अब तक किसी भी

तीन लाख यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी, हवाई अड्डों पर रहा था अफरातफरी का माहौल

डीजीसीए के आदेश का पालन होगा, जरूरी कदम उठाएंगे: इंडिगो

इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि वह नियामक के फैसले को गंभीरता से लेगी और आदेशों का पालन करेगी। एयरलाइन प्रवक्त ने कहा- 'गड़बड़ी के बाद से हमारी आंतरिक प्रणालियों की गहराई से समीक्षा की जा रही

एयरलाइन पर उड़ान बाधित करने के लिए नियामक द्वारा लगाए गए सबसे बड़े जुर्माने में से एक हैं, जबकि अन्य नियामक कार्रवाइयां भी अभूतपूर्व हैं।

तीन से पांच दिसंबर 2025 के दौरान इंडिगो की कुल 2,507 उड़ानें रद्द हुई थीं और 1,852 उड़ानों में देरी हुई थी। इस बड़े पैमाने पर परिचालन संकट के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर डीजीसीए ने एक चार सदस्यीय समिति गठित की थी। शनिवार को मंत्रालय ने बताया है कि समिति ने विस्तृत जांच के बाद तीन मुख्य कारणों की तरफ ध्यान

इंडिगो पर भारी-भरकम जुर्माना उड़ान बाधित करने के लिए किसी एयरलाइन पर लगाई गई रिकार्ड पेनल्टी

है ताकि एयरलाइन अपने परिचालन रिकार्ड को और मजबूत बना सके।' एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह यात्रियों की जरूरतों और सुविधाओं के लिए लगातार बेहतर काम करती रहेगी।

दिलाया है। इसमें सबसे प्रमुख है क्षमता का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हुए परिचालन। इसके अलावा अपर्याप्त नियामक तैयारियां, साफ्टवेयर की कमियां तथा प्रबंधन संरचना व परिचालन नियंत्रण में खामियों को अन्य कारण बताया गया है।

डीजीसीए ने बताया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को अपर्याप्त निगरानी के लिए चेतावनी दी गई है। सीओओ को भी बिंदर शोड्यूल को लेकर सही अनुमान नहीं लगाने को लेकर चेतावनी दी गई है।

Corporate Communications Directorate

DAINIK JAGRAN

KANPUR

17 JANUARY 2026

इंडिगो ने तीन से पांच दिसंबर के बीच रद्द उड़ानों का दिया रिफंड

मुंबई, प्रेट्र : डीजीसीए ने शुक्रवार को बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की तीन से पांच दिसंबर 2025 के बीच रद्द और देरी से चली उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों का टिकट रिफंड पूरी तरह से उनके खाते में वापस कर दिया गया है।

जिन यात्रियों की उड़ानें निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर रद्द की गई थीं, वे सभी नियमों के



तहत मुआवजे के हकदार हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि ऐसे यात्रियों को रिफंड के अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए क्लेम (दावा) करना होगा। इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के

लिए एक अतिरिक्त सुविधा भी दी है, जिसके तहत 5,000 रुपये के दो यात्रा वाउचर दिए जा रहे हैं, जिनकी वैधता 12 महीने है। यात्री उन नियमों के अनुसार मुआवजे के हकदार हैं, जो बोर्डिंग से इन्कार, उड़ान रद्द होने और उड़ान में देरी पर एयरलाइन द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित हैं।

Corporate Communications Directorate

DAINIK JAGRAN

KANPUR

17 JANUARY 2026

केवल 36 दिन ही शहर से उड़ सकी बेंगलुरु की नियमित फ्लाइट

जगरण संवाददाता, कानपुर : बेंगलुरु की फ्लाइट की नियमित सुविधा शहरवासियों को सिर्फ 36 दिन ही मिल सकी। शुरुवार से फिर यह फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन कर दी गई। इस कारण शुरुवार को यह फ्लाइट नहीं आ सकी। अब पहले की तरह इस फ्लाइट की सुविधा सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को तीन दिन ही मिल सकेगी। इस तरह कोलकाता समेत अन्य शहरों के लिए फ्लाइट की सुविधा जल्द मिलने के दावों के बीच हवाई यातायात की सुविधा में और कटौती कर दी गई है। शहर से अब दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट ही नियमित रह गई हैं। हैदराबाद की उड़ान की सुविधा सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुरुवार और रविवार को मिलती है।

- नहीं आई बेंगलुरु की उड़ान, फिर तीन दिन ही मिलेगी सुविधा
- अब दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट ही पहले की तरह नियमित



चक्रेरी एयरपोर्ट से बाहर निकलते यात्री ● जगरण आर्काइव

लंबे समय से शहरी बेंगलुरु की फ्लाइट की नियमित सुविधा की मांग कर रहे थे। क्रू की कमी और चेक इन सिस्टम में आई तकनीकी समस्या

से उड़ानों के निरस्त होने और देरी से आने व जाने की दिक्कत के बीच इंडिगो ने शहरियों को बेंगलुरु की फ्लाइट 10 दिसंबर से नियमित की

नई उड़ानें मिल नहीं रहीं, जो हैं उनमें भी कटौती

शहर से लगातार प्रमुख शहरों के लिए नई फ्लाइट की मांग उठती रही है। विभिन्न कारणों से यज्ञ से शुरू हुई फ्लाइट चालू होने के साथ बंद भी होती रही है। 1970 में एयरफोर्स के अधीन बने चक्रेरी स्थित एयरपोर्ट से पहली हवाई यात्रा सेवा शुरू हुई थी। यहां से पहली फ्लाइट दिल्ली के लिए चली थी। इसके बाद से कई बार फ्लाइट चालू और बंद हुई। मई 2023 में 150 करोड़ की लागत

से अहिरवा चक्रेरी में बने नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण हुआ था। इसके बाद यहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की हवाई यात्रा की शुरुआत हुई थी। नया टर्मिनल बनने से लोगों को लगा कि अब विमानन कंपनियां और भी शहरों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा शुरू करेंगी। इसी बीच 2024 के पहले माह जनवरी में ही बेंगलुरु की उड़ान बंद कर दी गई थी। अब फिर बेंगलुरु की उड़ान में कटौती हो गई।

थी। शेड्यूल के मुताबिक बेंगलुरु की फ्लाइट की सुविधा सोमवार, बुधवार, शुरुवार और रविवार को चार दिन और बढ़ाई गई थी। एयरपोर्ट निदेशक

प्रदीप यादव ने बताया कि बेंगलुरु की फ्लाइट की सुविधा अब यह सुविधा तीन दिन ही मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मिलेगी। इस फ्लाइट के

आने का समय 12:20 और जाने का समय 1:25 रहेगा।

लौड भरपूर था, बंद करने की वजह पता नहीं : इंडिगो ने बेंगलुरु की फ्लाइट की सुविधा फिर से तीन दिन ही करने की वजह स्पष्ट नहीं की है। हालांकि शहर से यात्रियों का भरपूर लोड मिल रहा था। विमानन कंपनी कभी 180 सीटर तो कभी 230 सीटर विमान संचालित करती है। अगर इस सप्ताह का यात्री लोड देखा जाए तो भरपूर लोड रहा है। सोमवार को बेंगलुरु से 107 यात्री आए और 152 गए। मंगलवार को आने वाले यात्रियों की संख्या 182 व जाने वालों की 198 रही। बुधवार को 144 आए और 140 गए, गुरुवार को आने वालों की संख्या 206 और जाने वालों की संख्या 199 रही।

हैदराबाद की फ्लाइट 54 मिनट देरी से आई

कानपुर : शुरुवार को हैदराबाद की फ्लाइट 54 मिनट और मुंबई की 36 मिनट देरी से आई। हैदराबाद की



फ्लाइट 12:45 बजे आकर दोपहर में 1:30 बजे जाती है। यह फ्लाइट 115

यात्री लेकर दोपहर 1:39 बजे आई और 173 यात्री लेकर 1:41 बजे गई। दिल्ली की फ्लाइट के आने का समय दोपहर दो और जाने का 2:40 बजे है। यह फ्लाइट दिल्ली से 142 यात्री लेकर दोपहर 1:53 बजे आई और 171 यात्री लेकर वापस 2:40 बजे गई। मुंबई की फ्लाइट दोपहर 2:35 बजे के बजाय 1:11 बजे 150 यात्री लेकर आई। यहां से 3:15 के बजाय 3:39 बजे 168 यात्री लेकर गई।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

DAINIK NAVJOYTI

JAIPUR

17 JANUARY 2026

इंडिगो की फ्लाइट में बवाल पायलट ने प्लेन उड़ाने से किया मना गुस्साए पैसेंजर चिल्लाने लगे

पायलट बोला: मेरी ड्यूटी टाइम लिमिट पूरी
हो चुकी, अब उड़ान नहीं भर सकता



एजेंसी/नई दिल्ली। मुंबई से थाईलैंड के क्राबी जा रही इंडिगो की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट 6ई 1085 में उस समय बवाल मच गया, जब पायलट ने विमान उड़ाने से मना कर दिया। यह उड़ान सुबह करीब 4:05 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन कई घंटों तक इसमें देरी होती रही। लगातार इंतजार कर रहे यात्रियों का धैर्य जवाब देने लगा। जब पायलट ने बताया कि उनकी ड्यूटी टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है और वह अब उड़ान नहीं भर सकते, तो यात्रियों का गुस्सा बढ़ गया। इसी वजह से फ्लाइट के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।

यात्रियों ने पायलट को अपशब्द कहे

पायलट के फैसले के बाद यात्रियों और केबिन कू के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ यात्री जोर-जोर से चिल्लाने लगे और सवाल करने लगे कि उनको छुट्टियों और बुकिंग का क्या होगा। वीडियो में एक यात्री को गुस्से में विमान के एग्जिट डोर पर लात मारते हुए देखा गया। उसने पायलट के खिलाफ अपशब्द भी कहे। यह पूरी घटना किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।

तीन घंटे देरी से उड़ान भरी

फ्लाइट ट्रेकिंग वेबसाइट फ्लाइटट्रेडर24 के अनुसार, यह फ्लाइट करीब तीन घंटे से ज्यादा की देरी से उड़ान भर सकी। जिसे सुबह लगभग 10 बजे क्राबी पहुंचना था, वह दोपहर करीब 1 बजे वहां पहुंची। इस देरी की वजह से कई यात्रियों की होटल बुकिंग, टूर प्लान और आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स प्रभावित हुईं। लोग परेशान थे क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा की पूरी योजना पहले से बना रखी थी। लंबा इंतजार, सही जानकारी की कमी और थकान ने यात्रियों को और ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया। इसी कारण हालात काबू से बाहर होते नजर आए।

कई कारणों से हुई देरी: इंडिगो

इस पूरे मामले पर इंडिगो एयरलाइंस ने आधिकारिक बयान जारी किया। कंपनी के अनुसार, उड़ान में देरी कई कारणों से हुई, जैसे विमान का देर से पहुंचना, हवाई वातावरण की भीड़ और कू का ड्यूटी टाइम लिमिट पूरा होना। एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा निबन्धों का पालन करना जरूरी है और पायलट ने वही किया। बयान में यह भी बताया गया कि दो यात्रियों ने प्रतीक्षा के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार किया। उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। इंडिगो ने कहा कि वह सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

CARRIER ALSO TOLD TO FURNISH ₹50 CR BANK GUARANTEE

DGCA Fines IndiGo ₹22 cr for December Flight Disruptions

Asks co to remove head of crew scheduling, sends warning letters to CEO, COO, other execs

Our Bureau

New Delhi: The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) on Saturday imposed a ₹22.2 crore penalty on IndiGo, after conducting a probe into massive disruptions in the airline's flight operations last month that affected hundreds of thousands of travellers.

The country's largest airline has also been ordered to furnish a ₹50 crore bank guarantee to ensure implementation of reforms in four areas: leadership and governance, manpower planning, digital systems and board oversight. The guarantee will be released in phas-

ses, only after the civil aviation regulator verified compliance at each stage.

The DGCA asked the airline to remove head of crew scheduling Jason Herter, and served warning letters to multiple executives, including chief executive Pieter Elbers and chief operating officer Isidro Porqueras.

The DGCA will also undertake an internal inquiry on the instruction of the Ministry of Civil

We are in receipt of order. In-depth review of the robustness and resilience of the internal processes at IndiGo has been underway since the disruption to ensure that the airline emerges stronger out of these events

INDIGO STATEMENT

Aviation to identify and implement systemic improvements within the regulator.

The aviation regulator in December set up an inquiry committee after IndiGo cancelled more than 5,000 flights, as the no-frills airline fell short of crew following the implementation of new rest rules for pilots.

The cancellations by the airline, which has more than 60% share of the domestic market, at the peak of holiday and wedding season threw the sector into chaos.

In a very unusual move, the airline's response to the DGCA order came from the board of directors of InterGlobe Aviation, which operates IndiGo.

"We are in receipt of the order. In-depth review of the robustness and resilience of the internal processes at IndiGo has been underway since the disruption to ensure that the airline emerges stronger out of these events in its otherwise pristine record of 19+ years of operations," it said in a statement.

Planning Deficiencies ▶▶ 7



Planning Deficiencies

▶▶ **From Page 1**

In its investigation, the DGCA found that the airline's management failed to adequately identify planning deficiencies, maintain sufficient operational buffers and effectively implement the new pilot rest hour provisions.

"There was an overriding focus on maximising utilisation of crew, aircraft and network resources, which significantly reduced roster buffer margins," the DGCA said. "Crew rosters were designed to

maximise duty periods, with increased reliance on deadheading (crew travelling as passengers on flights to get to their next assignment), tail swaps (changing aircraft), extended duty patterns and minimal recovery margins. This approach compromised roster integrity and adversely impacted operational resilience."

These lapses resulted in widespread flight delays and large-scale cancellations, causing inconvenience to passengers, according to the findings.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

FINANCIAL EXPRESS

DELHI

18 JANUARY 2026

DGCA slaps ₹22.2-cr fine on IndiGo

NITIN KUMAR
New Delhi, January 17

THE DIRECTORATE GENERAL of Civil Aviation (DGCA) on Saturday imposed penalties totalling ₹22.2 crore on IndiGo and initiated disciplinary action against several senior executives after a probe found that aggressive operational optimisation, weak regulatory preparedness and systemic management failures led to large-scale flight disruptions in early December 2025.

The action follows the

cancellation of 2,507 IndiGo flights and delays to another 1,852 services between December 3 and 5, 2025, leaving over three lakh passengers stranded across airports.

Acting on directions from the Ministry of Civil Aviation (MoCA), the DGCA had constituted a four-member committee to investigate the episode. Responding to the regulatory action, IndiGo said it would take "full cognisance" of the findings.

Beyond financial penal-

ties, the regulator has ordered IndiGo to furnish a ₹50-crore bank guarantee under a newly instituted IndiGo Systemic Reform Assurance Scheme (ISRAS).

The guarantee will be released in phases, strictly linked to DGCA-verified implementation of reforms across leadership and governance, manpower planning and fatigue-risk management, digital systems and operational resilience, and sustained board-level oversight over a 9-15 month period.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN

DELHI

18 JANUARY 2026

कार्रवाई : इंडिगो पर डीजीसीए ने 22 करोड़ का जुर्माना ठोका

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने और देरी से संचालित होने के मामलों में देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो पर 22.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी के तीन अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है।

पिछले साल तीन से पांच दिसंबर के बीच इंडिगो की 2507 उड़ानें रद्द हुई थीं, जबकि 1852 उड़ानें देरी से संचालित की गई थीं। इससे देशभर में तीन लाख से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

डीजीसीए ने यह कार्रवाई जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की है। इंडिगो की उड़ान सेवाएं बड़े पैमाने पर बाधित होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर डीजीसीए ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच में सामने आया कि इंडिगो ने उड़ानों की योजना बनाने में गंभीर चूक की। जरूरत से ज्यादा उड़ानों का दबाव

तीन वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी



■ डीजीसीए ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को उड़ान संचालन और संकट प्रबंधन की समुचित निगरानी न करने पर चेतावनी दी है

■ जवाबदेह प्रबंधक और मुख्य परिचालन अधिकारी को शीतकालीन समय-सारिणी 2025 और संशोधित उड़ान इयूटी समय सीमा (एफडीटीएल) नियमों के प्रभाव का सही आकलन न करने के लिए चेतावनी है

■ वरिष्ठ उपाध्यक्ष (ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर) को मौजूदा परिचालन जिम्मेदारियों से हटाने और भविष्य में किसी जवाबदेह पद पर तैनाती न करने के निर्देश दिए गए हैं

डाला गया, जबकि स्टाफ और सिस्टम से जुड़ी कोई ठोस तैयारी नहीं गई थी।

लापरवाही बनी वजह : जांच समिति ने माना कि प्रबंधन स्तर पर भारी लापरवाही के कारण यह संकट खड़ा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो ने उड़ानों की योजना बनाते समय पर्याप्त बैकअप नहीं रखा। नए इयूटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) नियमों को

सही तरीके से लागू नहीं किया गया और कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार डाला गया। पायलट और क्यू की इयूटी इस तरह तय की गई थी कि मामूली गड़बड़ी होने पर पूरा सिस्टम चरमरा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि देशभर में बड़ी संख्या में उड़ानें या तो रद्द करनी पड़ीं या फिर 10 से 16 घंटे की देरी से संचालित हुईं।

IndiGo hit with record ₹22cr fine for Dec chaos

Neha LM Tripathi

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: India's aviation regulator on Saturday imposed a record ₹22.2 crore penalty on IndiGo and issued warnings to six senior executives, including the chief operating officer, after its inquiry found the airline's "overriding focus on maximising utilisation" of crew and aircraft through aggressive cost-cutting drove December's operational meltdown that stranded over 300,000 passengers.

The Directorate General of Civil Aviation's (DGCA) four-member inquiry committee determined that "over-optimisation of operations, inadequate regulatory preparedness along with deficiencies in system software support and shortcomings in management structure and operational control" caused the crisis that saw 2,507 flights cancelled and 1,852 delayed between December 3 and 5 last year.

The findings confirm warnings from pilot associations and aviation experts that IndiGo's pursuit of maximum crew and aircraft utilisation with minimal operational buffers created a crisis that it could have avoided, especially since the tighter crew

IndiGo's regulatory blues

Fines, bank deposit, ultimatums — airline taken to task over Dec 3-5 mayhem

FINANCIAL PENALTIES: ₹22.2 CR One-time violations: ₹1.80CR 6 systemic failures @ ₹30 lakh each, including: <ul style="list-style-type: none"> ● FDTL compliance schemes violation; ● Failing to balance commercial vs crew welfare; ● Improper operational control; ● Management accountability lapses. 	INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY CEO PIETER ELBERS Cautioned for inadequate oversight COO ISIDRE PORQUERAS OREA Warning for failure to assess impact SVP OPS CONTROL JASON HERTER Removed from role, barred from accountable positions WARNINGS TO THREE OTHER EXECUTIVES <ul style="list-style-type: none"> ● Deputy head, Flight Operations ● AVP, crew Resource Planning ● Director, Flight Operations
Continued non-compliance: ₹20.40 CR <ul style="list-style-type: none"> ● ₹30 lakh per day × 68 days (Dec 5 - Feb 10) for violating night-duty limitations 	Deposit required: ₹50 CR <ul style="list-style-type: none"> ● To be refunded once airline carries out operational corrections



AIRLINE BOARD RESPONSE

"The Board and Management of IndiGo are committed to taking full cognizance of the orders and will, in a thoughtful and timely manner, take appropriate measures. An in-depth review of the robustness and resilience of internal processes has been underway since the disruption." — INDIGO BOARD STATEMENT, Jan 17, 2026

rest (FDTL) rules were unveiled more than two years before they came into effect.

"Crew rosters were designed to maximise duty periods, with increased reliance on dead-heading, tail swaps, extended

duty patterns, and minimal recovery margins. This approach compromised roster integrity and adversely impacted operational resilience," the committee stated, according to a government release.

The airline's management "failed to adequately identify planning deficiencies, maintain sufficient operational buffer, and effectively implement the revised Flight Duty Time Limita-

continued on →10

DGCA FINES INDIGO

tion provisions," resulting in "widespread flight delays and large-scale cancellations," according to the inquiry report submitted to the civil aviation ministry.

The regulator warned six senior executives, including chief operating officer Isidre Porqueras Orea, and ordered the senior vice president for operations control centre to be removed from operational responsibilities and barred from any accountable position, while chief executive Pieter Elbers received a formal caution for inadequate oversight.

It also asked the airline to deposit ₹50 crore in bank guarantees, which will be refunded as and when the airline carries out necessary corrections in its operations.

IndiGo's board issued a brief statement on Saturday, saying it was "committed to taking full cognizance of the orders" and would "in a thoughtful and timely manner, take appropriate measures." The airline said an "in-depth review of the robustness and resilience of the internal processes at IndiGo has been underway since the disruption to ensure that the airline emerges stronger out of these events in its otherwise pristine record of 19+ years of operations."

The airline, which commands 60% of India's domestic market and operates over 2,000 flights daily, has been directed to curtail operations and submit fortnightly compliance reports.

While the penalty is unprecedented in India's aviation sector, it represents just 0.31% of the ₹7,263 crore net profit the airline recorded in the financial year ended March 2025. Aviation experts likened it to a slap on the wrist for a carrier that generates billions in annual profits.

"The DGCA speaks of compensation, but a ₹22 crore penalty is negligible for an airline of IndiGo's size. It is roughly equivalent to the cost of employing about 20 pilots, which means absolutely nothing to the airline," said Mark Martin of Martin Consultancy.

A former senior bureaucrat and a serving government official, both requesting anonymity, concurred that the fine was mild. "The fine amount doesn't do justice to the issues faced by lakhs of passengers," the former official said.

According to an official who asked not to be named, the airline's exemption from the FDTL rules will not be extended beyond February 10. The FDTL rules involve stricter limits on pilot duty hours and mandatory rest periods,

including increased weekly rest from 36 to 48 hours, expanded night-duty definitions, and restrictions on night landings to two per week from six previously.

DGCA did not respond to requests for a comment on this aspect. The regulator directed that senior vice president for operations control centre, Jason Herter be relieved of operational responsibilities and barred from any accountable position for "failure in systemic planning and timely implementation of revised FDTL provisions." Warnings were also issued to the deputy head of flight operations, assistant vice president for crew resource planning, and director of flight operations.

IndiGo has been directed to take "appropriate action against any other personnel identified through its internal inquiry and submit a compliance report to DGCA." On the ministry's directions, DGCA said it has also launched an internal inquiry "to identify and implement systemic improvements within the DGCA," a rare acknowledgment that regulatory oversight failures contributed to the crisis.



Corporate Communications Directorate

HINDU

DELHI

18 JANUARY 2026



DGCA slaps ₹22.2 cr. penalty on IndiGo for disruptions

Aviation safety regulator Directorate General of Civil Aviation (DGCA) on Saturday imposed a penalty of ₹22.2 crore on IndiGo airline for flight disruptions in December 2025, citing the overstretching of flight crew as the key factor behind the airline's operational meltdown. It has also issued a warning to CEO Pieter Elbers and COO Isidre Porqueras who were served a showcause notice and has ordered the removal of Senior Vice President, Operational Control Centre, Jason Herter from his current position "for failure in systemic planning and timely implementation" of revised duty and rest norms for pilots which kicked in from November 1.

INDIGO SAYS COMMITTED TO TAKING FULL COGNISANCE OF DGCA ORDERS

For December mess, DGCA fines IndiGo Rs 22 cr, warns top brass

Told to pledge Rs 50 cr bank guarantee, relieve head of operations control

Sukalp Sharma
New Delhi, January 17

THE AVIATION regulator Saturday slapped the country's largest airline IndiGo with a Rs 22.20 crore penalty, asked it to pledge a Rs 50 crore bank guarantee, and warned its CEO and COO, among others, for the management's poor preparation ahead of the implementation of the new pilot test rules, which led to a massive disruption in December with

2,500 flight cancellations and 1,850 delays.

The enforcement actions by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) and strong strictures against the IndiGo management are based on the findings of a four-member inquiry committee tasked with a comprehensive review and assessment of the circumstances that led to the crisis in the first week of December. The panel had submitted a report to the DGCA on December 26, and the



IndiGo flight disruptions affected thousands last month. FILE

findings and recommendations were forwarded to the Ministry of Civil Aviation (MoCA).

The cumulative fine of Rs 22.20 crore is the highest-ever regulatory penalty imposed by

the DGCA on an airline, according to sources, and is slightly higher than IndiGo's average daily net profit for financial year 2024-25. The Rs 50 crore bank guarantee pledged to the DGCA would be released by it in phases after the airline implements measures to ensure compliance with DGCA directives and long-term systemic correction. Besides the warnings to CEO Pieter Elbers and COO Isidre Porqueras, the DGCA also directed the airline to relieve Jason Herter, senior vice president of IndiGo's operations control centre (OCC), of current operational responsibilities.

»CONTINUED ON PAGE 2

IndiGo

The airline's board said along with the IndiGo management, it is "committed to taking full cognizance of the orders and will, in a thoughtful and timely manner, take appropriate measures". Given that the airline commands a domestic market share of around 65 per cent, the disruption had brought India's civil aviation operations to their knees.

The inquiry committee had concluded that the primary causes for the disruption were over-optimisation of operations, inadequate preparedness along with deficiencies in system software support for the revised Flight Duty Time Limitation (FDTL) provisions, and shortcomings in IndiGo's management structure and operational control. Civil Aviation Minister K Rammohan Naidu had assured stringent action based on the report against those found responsible for the IndiGo meltdown, saying government action will "set an example".

"The Committee observed that the airline's management failed to adequately identify planning deficiencies, maintain sufficient operational buffers, and effectively implement the revised FDTL provisions. These lapses resulted in widespread flight delays and

large-scale cancellations, causing inconvenience to passengers," MoCA said Saturday.

"The Inquiry further noted an overriding focus on maximising utilisation of crew, aircraft, and network resources, which significantly reduced roster buffer margins. Crew rosters were designed to maximise duty periods, with increased reliance on dead-heading, tail swaps, extended duty patterns, and minimal recovery margins. This approach compromised roster integrity and adversely impacted operational resilience. The inquiry also included within its purview long term reform measures addressing systemic issues so that such incidents do not occur in the future and passengers are not put to any inconvenience," it said.

"Action against officials of Interglobe Aviation (IndiGo): Caution to the CEO for inadequate overall oversight of flight operations and crisis management, Warning to the Accountable Manager (COO) for failure to assess the impact of Winter Schedule 2025 and the revised FDTL CAR (civil aviation requirement) leading to widespread disruptions and Warning to the Senior Vice President (OCC) with directions to relieve him of current operational responsibilities and not to assign any accountable position, for failure in systemic planning and timely implementation of

revised FDTL provisions," said MoCA, adding that warnings have also been issued to a few other senior IndiGo officials.

As for financial penalties, one-time fines totalling Rs 1.80 crore—penalty of Rs 30 lakh each on six counts of non-compliance—has been imposed on the airline by the DGCA. Additionally, IndiGo has also been slapped a daily penalty of Rs 30 lakh for 68 days—December 5 to February 10—which comes out to Rs 20.40 crore.

"The Bank Guarantee-linked reform framework of Rs 50 crore titled the IndiGo Systemic Reform Assurance Scheme (ISRAS) for IndiGo, under which phased release of the Bank Guarantee is strictly tied to DGCA-verified implementation of reforms across four pillars—leadership and governance (Rs 10 crore upon certification within 3 months), manpower planning, rostering and fatigue-risk management (Rs 15 crore linked to initial and sustained compliance over 6 months), digital systems and operational resilience (Rs 15 crore upon acceptance of upgrades and safeguards within 9 months), and board-level oversight with sustained compliance (Rs 10 crore after six months of continued adherence over a 9–15 month period)," the MoCA release said detailing the bank guarantee action against IndiGo.

December 5 was the day

when the disruption peaked with over 1,600 of the airline's 2,300-plus daily flights getting cancelled, and the DGCA allowed IndiGo a temporary exemption till February 10 from a few night duty-related changes in the new FDTL rules for pilots, which helped the airline swiftly stabilise operations over the course of the next few days. On January 9, IndiGo was ordered to curtail its approved domestic flight schedule by 10 per cent. An internal inquiry is also being undertaken by the regulator to identify and implement systemic improvements within the DGCA.

The regulator placed its oversight teams at the airline's headquarters to monitor network and crew operations as the crisis subsided, and summoned the IndiGo top brass on multiple occasions during and after the crisis. The airline's CEO and COO were also issued show-cause notices by the regulator in view of the operational meltdown. The DGCA also terminated the services of four flight operations inspectors (FOIs) responsible for oversight on IndiGo and the airline's preparation for the new FDTL rules.

In review meetings with the DGCA and MoCA, IndiGo had accepted that the disruptions arose "primarily from misjudgement and planning gaps in implementing" the second phase of new FDTL rules.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

JANSATTA

DELHI

18 JANUARY 2026

उड़ान व्यवधान के लिए इंडिगो पर 22.2 करोड़ का जुर्माना

मुंबई, 17 जनवरी (भाषा)।

विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने पिछले महीने हुई व्यापक उड़ान व्यवधानों के लिए शनिवार को इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और कंपनी के प्रमुख पीटर एल्बर्स के साथ-साथ दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की। इसके अलावा, विमानन नियामक ने एअरलाइन को अपने निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधार के लिए 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इंडिगो ने दिसंबर की शुरुआत में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दीं क्योंकि एअरलाइन पायलटों के वास्ते नए उड़ान ड्यूटी मानदंडों को लागू

करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थी। उड़ानें रद्द किए जाने से देश भर में हजारों यात्री फंस गए। इंडिगो के परिचालन में बड़े पैमाने पर व्यवधान के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्राह्मणे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया, ताकि ऐसे व्यवधानों के कारणों की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन किया जा सके।

इस समिति ने पिछले साल 27 दिसंबर को डीजीसीए को अपनी रपट सौंपी थी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आठ दिसंबर को राज्यसभा में इंडिगो के व्यापक परिचालन व्यवधानों पर कहा था कि हम इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम जांच कर रहे हैं। हम मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे।

Corporate Communications Directorate

LOKH SATYA

DELHI

18 JANUARY 2026

एवशन: इंडिगो पर 22.20 करोड़ का जुर्माना, शीर्ष प्रबंधन पर गिरी गाज

● दिसंबर में उड़ानें रद्द और विलंब से रहने का मामला

नई दिल्ली, लोकसत्य। भारतीय विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है। उड़ानों के रद्द होने और देरी के मामले में इंडिगो पर 22 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हुई थीं या विलंब से रही थीं। एयरलाइन को डीजीसीए के पक्ष में बैंक गारंटी देने को कहा गया है। डीजीसीए ने इंडिगो पर न केवल वित्तीय दंड लगाया है, बल्कि एयरलाइन के शीर्ष प्रबंधन को कड़ी फटकार भी लगाई है। इसमें सीईओ



को चेतावनी और एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष को परिचालन जिम्मेदारी से हटाने का निर्देश शामिल है।

● 2,507 उड़ानें रद्द हुईं: यह कार्रवाई 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच इंडिगो की उड़ानों में आई भारी बाधा के बाद की गई है। इस दौरान एयरलाइन की 2,507 उड़ानें रद्द हुईं

और 1,852 उड़ानों में देरी हुई, जिससे हवाई अड्डों पर 3 लाख से अधिक यात्री फंस गए थे।

● जांच समिति ने दोषी पाया: डीजीसीए द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने पाया कि यह संकट संसाधनों के 'ओवर-ऑप्टिमाइजेशन' (अत्यधिक उपयोग) का परिणाम था।

CEO, SENIOR OFFICIALS WARNED

Flight chaos lands IndiGo ₹22.2-cr penalty

Flight chaos costs IndiGo Rs 22.2 crore

MPOST BUREAU



TURBULENCE

» Besides, the regulator had directed the airline to furnish a Rs 50-crore bank guarantee to ensure compliance with its directives as well as long-term systemic correction

» In early December, IndiGo cancelled hundreds of flights across the country as the airline was not adequately prepared to implement the new flight duty norms for pilots

MUMBAI: Airlines regulator DGCA on Saturday slapped Rs 22.20-crore penalty on IndiGo and warned its CEO Pieter Elbers and two other senior executives for last month's flight disruptions, which the watchdog blamed on inadequate regulatory preparedness and management structure shortcomings.

Besides, the regulator had directed the airline to furnish a Rs 50-crore bank guarantee to ensure compliance with its directives as well as long-term systemic correction.

In early December, IndiGo cancelled hundreds of flights

across the country as the airline was not adequately prepared to implement the new flight duty norms for pilots.

Last month, the airline was provided relaxation till February 10 to comply with the new Flight Duty Time Limitation

(FDTL) norms.

In a not-so-common move, the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has imposed a total penalty of Rs 20.40 crore for the non-compliance for the period of 68 days from December 5, 2025 to February 10, 2026.

The amount translates to Rs 30 lakh fine for each day during the 68-day period.

"In addition to individual enforcement actions, a one-time financial penalty (on six counts) is imposed on M/s Indigo Airlines for non-compliance with directions issued under Rule 133A of the Aircraft Rules, 1937," the DGCA said in a statement.

While the regulator imposed a financial penalty of Rs 30 lakh for the airline's "failure to establish and effectively implement a scheme for compliance with limits of Flight Time, Flight Duty Period, Duty Period and Rest Periods; inadequate buffer margins in roster planning", **Continued on P4**

another Rs 30-lakh financial penalty has been slapped for "failure of accountable management to ensure overall functioning, financing, and conduct of operations to DGCA standards, as per the statement.

Similarly, Rs 30-lakh financial penalty has been imposed for "improper delegation and exercise of operational control responsibilities contrary to approved methods" while a financial penalty of Rs 30 lakh has been imposed for "failure of accountable management to ensure overall functioning, financing, and conduct of operations to DGCA standards".

IndiGo Chief Operating Officer Isidre Porqueras is the Accountable Manager at the airline.

According to the statement, IndiGo has been ordered to pledge a bank guarantee of Rs 50 crore in favour of DGCA, to ensure compliance with the directives and long-term systemic correction.

"The bank guarantee-linked reform framework of Rs 50 crore titled the IndiGo Systemic Reform Assurance Scheme (ISRAS) for IndiGo, under which phased release of the bank guarantee is strictly tied to DGCA-verified implementation of reforms," it said.

These reforms will be across four key elements -- leadership and governance (Rs 10 crore upon certification within three months), and manpower planning, rostering and fatigue-risk management (Rs 15 crore linked to initial and sustained compliance over six months),

Of the remaining amount, Rs 15 crore will be linked to digital systems and operational resilience upon acceptance of upgrades and safeguards within nine months, and Rs 10 crore related to board-level oversight with sustained compliance after six months of continued adherence over a 9-15 month period.

"Release of the bank guarantee will be contingent upon independent verification and certification by DGCA at each stage," the statement said.

In the unprecedented disruptions from December 3-5, DGCA said 2,507 flights were cancelled and 1,852 flights were delayed impacting over 3 lakh passengers at various airports.

The enforcement actions have been taken following a detailed probe by a four-member committee of DGCA officials. The panel had submitted its report to the the regulator late last month.

The penalties are one of the biggest imposed by the regulator so far on any airline for flight disruptions, while other regulatory actions are also unprecedented.

Following the disruptions last month, the DGCA had also curtailed IndiGo's winter schedule flights by 10 per cent.

The committee's findings and recommendations were forwarded to the MoCA. After due deliberations, DGCA issued warning to CEO Pieter Elbers for inadequate overall oversight of flight operations and crisis management, along with issuing warning to the accountable manager (COO) for failure to assess the impact of winter schedule 2025 and the revised FDTL CAR leading to widespread disruptions.

A warning has also been issued to IndiGo Senior Vice President (OCC) with directions to relieve him of current operational responsibilities and not to assign any accountable position, for failure in systemic planning and timely implementation of revised FDTL provisions, DGCA said in the statement.

Additionally, warnings have also been issued to deputy head, flight operations, AVP, crew resource planning, and director, flight operations for operational, supervisory, manpower planning, and roster management lapses, the DGCA added.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

MORNING STANDARD

DELHI

18 JANUARY 2026

IndiGo slapped with ₹22-cr penalty for last month's chaos

S LALITHA @ New Delhi

THE Directorate General of Civil Aviation (DGCA) on Saturday slapped a penalty of ₹22.20 crore on Indigo for last month's massive flight disruptions. Additionally, the regulator directed the airline to furnish ₹50 crore bank guarantee to ensure compliance with its directives and long-term systemic correction.

The aviation watchdog also released the findings of a four-member committee constituted to investigate the disruptions that occurred between December 3 and 5. The committee



identified four key reasons: over-optimisation of operations, inadequate regulatory preparedness, and deficiencies in system software support and shortcomings in both the management structure and opera-

₹20.4 crore for regulatory non-compliance

The ₹22.2 crore penalty includes a one-time systemic charge of ₹1.8 crore, along with additional ₹20.4 crore for continued non-compliance with regulatory requirements from Dec 5 to Feb 10. The DGCA praised the airline for quick restoration of normalcy

tional control by the airline.

The committee observed that the airline's management failed to adequately identify planning deficiencies, maintain sufficient operational buffer and effectively implement the revised

Flight Duty Time Limitation (FDTL) provisions. These lapses resulted in widespread flight delays and large-scale cancellations, causing inconvenience to passengers.

Recommending long-term reform measures to prevent such incidents, the committee, in its report, said, "The findings underscore the need for balanced operational planning, robust regulatory preparedness and effective management oversight to ensure sustainable operations and passenger safety and convenience."



The report further noted that the airline's overriding focus was on maximising utilisation of crew, aircraft, and network resources, which significantly reduced roster buffer margins.

The DGCA has ordered the airline to relieve the Senior Vice President for operations control centre of current operational responsibilities. It warned Inter-globe Aviation's chief executive office Pieter Elbers for inadequate oversight over flight operations and crisis management.

एयरलाइन संकट में इंडिगो दोषी, 20 करोड़ का फाइन

Maneesh Aggarwal
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली : पिछले महीने 3 से 5 दिसंबर के बीच देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइटों कैसल और डिले होने के मामले में डीजीसीए ने एयरलाइंस को अपनी बढ़ती फ्लाइटों और इनके मैनेजमेंट को ठीक से ना संभाल पाने, रोस्टर के गड़बड़ाने, पायलटों का पर्याप्त बफर ना होने और एफडीटीएल को ठीक से लागू करने में विफल रहने का दोषी पाया है।

डीजीसीए ने इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने भविष्य में सुधार के लिए डीजीसीए के पक्ष में इंडिगो से इंडिगो सिस्टमेटिक रिफॉर्म एश्योरेंस स्कैम (ISRAS) के तहत 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी जमा करने के आदेश दिए हैं। मामले में पांच दिसंबर को गठित की गई चार अधिकारियों की कमेटी ने डीजीसीए को यह रिपोर्ट 26 दिसंबर को सौंप दी थी। इसके बाद डीजीसीए के डीजी फैज अहमद किदवाई समेत अन्य अधिकारियों ने इसकी स्टडी की और रिपोर्ट के आधार



पर इंडिगो के उपर पेनेल्टी लगाने समेत अन्य ऐक्शन लेने के आदेश दिए। रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को भेज दी गई है।

DGCA रिपोर्ट में CEO, COO को पद से हटाने जैसे कोई सख्त निर्देश नहीं है

मामले में डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एब्लस और सीओओ को पद से हटाने जैसी कोई सख्त अनुशंसा नहीं की है। इसमें सीईओ को फ्लाइट ऑपरेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट की ठीक से निगरानी ना करने का आरोपी मानते हुए उन्हें कॉशन नोटिस थमाया गया है। जबकि सीओओ को विंटर शेड्यूल और लैगू हुए नए एफडीटीएल नियमों के प्रभाव का आकलन करने में विफल मानते हुए उन्हें चेतावनी दी गई है। विंग ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओसीसी) के सीनियर वाइज प्रेजिडेंट को फ्लाइटिंग ऑपरेशंस जिम्मेदारियों से मुक्त करने का आदेश दिया गया है।

IndiGo fined ₹22.2 cr for December chaos

RAJESH KUMAR
New Delhi

Holding the management responsible, the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has imposed financial penalties amounting to ₹22.20 crore on IndiGo and taken strict enforcement action against its senior management after a probe found serious planning, operational and regulatory lapses for a massive network-wide operational disruption between December 3 and 5 last year. Additionally, IndiGo has been ordered to pledge a bank guarantee of ₹50 crore in favour of DGCA, to ensure compliance with the directives and long term systemic correction.

The disruption resulted in the cancellation of 2,507 flights and delays of 1,852 flights, causing inconvenience to over three lakh passengers stranded at various airports.

DGCA has also issued caution to IndiGo's CEO for inadequate oversight and crisis management.

CONTINUED ON >> P4



Stranded passengers searching for their luggage at the Bengaluru airport in December last year due to IndiGo cancellations

FINE EXPLAINED

- Daily Penalty : ₹30,00,000
- Total Days of Non-Compliance : 68 days
- Total Penalty for Continued Non-Compliance: 68 × ₹30,00,000 = ₹20,40,00,000/- (Rupees Twenty Crore Forty Lakh Only)

COMPONENT AMOUNT

- One-time systemic penalties: ₹1.80 crore
- Continued non-compliance penalty: ₹20.40 crore
- Total Penalty Imposed: ₹22.20 crore

IndiGo fined ₹22.2 cr for December chaos

The Accountable Manager (COO) has been warned by the DGCA for failing to assess the impact of the Winter Schedule 2025 and revised FDTL norms.

The regulator has also warned the senior vice president (Operations Control Centre) and directed that he be relieved of current operational responsibilities, barring him from holding any accountable position.

According to a statement issued by the DGCA, it has imposed ₹1.80 crore in one-time penalties for six instances of non-compliance with Civil Aviation Requirements (CARs), including failure to ensure effective implementation of FDTL norms, improper delegation of operational control, and shortcomings in accountable management. In addition, the airline was fined Rs 20.40 crore for continued non-compliance over 68 days between December 5, 2025 and February 10, 2026, at a daily penalty of ₹30 lakh.

Warnings have further been issued to the deputy head-flight operations, AVP-crew resource planning and director-flight operations for lapses in manpower planning and roster management. IndiGo has been instructed to take action against other personnel identified through its internal inquiry and submit a compliance report to DGCA.

Beyond penalty, DGCA has directed IndiGo to furnish a Rs 50 crore bank guarantee under a newly instituted IndiGo Systemic Reform Assurance Scheme (ISRAS). The guarantee will be released in phases based on DGCA-certified implementation of reforms across four areas: leadership and governance, manpower planning and fatigue-risk management, digital systems and operational resilience, and sustained board-level oversight. The chairman and members of the board of directors of IndiGo, in a statement confirmed they have received the DGCA's orders and will take appropriate measures. "We would like to take this opportunity to inform all of our stakeholders, particularly our valued customers, that the board and the management of IndiGo are committed to taking full cognizance of the orders and will, in a thoughtful and timely manner, take appropriate measures," the statement said.

A four-member inquiry committee, set up by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) on the directions of the Ministry of Civil Aviation (MoCA), found that the primary causes were over-optimisation of operations, inadequate regulatory preparedness, weak software systems, and shortcomings in management oversight at IndiGo. The committee members examined the airline's operations, spoke to key officials, and reviewed its planning and crew management systems. The inquiry found that the disruptions were not caused by bad weather alone but by deeper operational problems within the airline.

The inquiry report identified over-optimisation of operations, inadequate regulatory preparedness, and deficiencies in planning software and management oversight as the primary causes of the disruption. It found that IndiGo failed to maintain adequate operational buffers and did not effectively implement revised Flight Duty Time Limitation (FDTL) norms.

The Committee observed that the airline's management failed to adequately identify planning deficiencies, maintain sufficient operational buffer, and effectively implement the revised Flight Duty Time Limitation (FDTL) provisions. These lapses resulted in widespread flight delays and large-scale cancellations, causing inconvenience to passengers.

The inquiry further noted an overriding focus on maximising utilisation of crew, aircraft, and network resources, which significantly reduced roster buffer margins. Crew rosters were designed to maximise duty periods, with increased reliance on dead-heading, tail swaps, extended duty patterns, and minimal recovery margins. This approach compromised roster integrity and adversely impacted operational resilience. The inquiry also included within its purview long term reform measures addressing systemic issues so that such incidents do not occur in the future and passengers are not put to any inconvenience.

The findings underscore the need for balanced operational planning, robust regulatory preparedness, and effective management oversight to ensure sustainable operations and passenger safety and convenience.

DGCA acknowledged that IndiGo restored operations swiftly and complied with refund and compensation norms. On MoCA's directions, the airline also issued a Rs 10,000

'Gesture of Care' voucher with a 12-month validity to passengers affected by cancellations or delays exceeding three hours during the disruption period. The DGCA said the action was taken after reviewing the airline's operational lapses that led to widespread inconvenience for passengers during the period.

The disruption at India's largest airline which carries over 60 per cent of the country's domestic air passengers has been primarily triggered by crew shortages following the implementation of the new Flight Duty Time Limitation (FDTL) norms. The second and final phase of the revised crew duty and rest regulations came into effect last month, leaving IndiGo inadequately prepared for the transition.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

SWATANTRA BHARAT

LUCKNOW

17 JANUARY 2026

इंडिगो देगा यात्रियों को पूरा रिफंड और दस हजार का मुआवजा

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 3 से 5 दिसंबर, 2025 के बीच

■ डीजीसीए की सख्ती का असर

परिचालन संबंधी गंभीर व्यवधानों से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने के संबंध में इंडिगो एयरलाइंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। डीजीसीए ने कहा है कि इंडिगो ने पुष्टि की है कि निर्धारित अवधि के दौरान रद्द हुई उड़ानों के लिए सभी रिफंड पूरी तरह से संसाधित कर दिए गए हैं और मूल

भुगतान विधि में वापस कर दिए गए हैं। यात्री डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के खंड 3, श्रृंखला एम, भाग चार के तहत मुआवजे के हकदार हैं, जो बोर्डिंग से इनकार, रद्द होने और देरी से प्रभावित यात्रियों के लिए सुविधाओं का प्रावधान करता है। जिन यात्रियों की उड़ानें निर्धारित प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर रद्द हो गईं, वे लागू होने की स्थिति में, एयरलाइन द्वारा प्रदान किए गए एक विशेष लिंक के माध्यम से अतिरिक्त मुआवजे का दावा कर सकते हैं। अतिरिक्त सहायता उपाय के रूप में, इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए देखभाल का प्रतीक (जीओसी) शुरू किया है।

Corporate Communications Directorate

STATESMEN

DELHI

18 JANUARY 2026

Wings India '26 to showcase future of global aviation

STATESMAN NEWS SERVICE

New Delhi, 17 January

Wings India 2026, Asia's largest civil aviation event, will be formally launched with a grand inaugural ceremony led by Minister of Civil Aviation Rammohan Naidu, in the presence of high-level dignitaries from India and abroad.

The launch will mark the beginning of a landmark four-day global aviation gathering scheduled to be held from 28 to 31 January at Begumpet Airport, Hyderabad, the Ministry of Civil Aviation said on Saturday. Anchored around the theme "Indian Aviation: Paving the Future – From Design to Deployment, Manufacturing to Maintenance, Inclusivity to Innovation and Safety to Sustainability", Wings India 2026 will highlight India's rapidly expanding aviation landscape, its growing global footprint, and its vision to emerge as a key hub for manufacturing, services, innovation and sustainable

aviation solutions. Wings India 2026 will feature an expansive international exhibition, static aircraft displays, flying and aerobatic shows, a high-level international conference, CEO roundtables, B2B and B2G meetings, an aviation job fair, awards ceremony, and vibrant cultural programmes. Delegates and participants from across the world are expected, reinforcing the event's stature as a premier global aviation forum.

Prominent domestic and international stakeholders from across the aviation value chain will participate, including airlines, aircraft and engine manufacturers, MROs, airport developers, OEMs, technology providers, training institutions and service partners.

The event will serve as a convergence point for policymakers, industry leaders, innovators and investors to deliberate on emerging trends, opportunities and collaborative pathways shaping the future of civil aviation in India and worldwide.



IndiGo 'clears' refunds but many 'lose out'

OUR BUREAU

New Delhi: IndiGo has fully processed the refunds for flight cancellations in early December, the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) said on Friday.

However, the disbursement of compensation to affected passengers is still underway, an airline source said.

"IndiGo informed that all refunds for IndiGo flight cancellations during the period of 3rd to 5th Dec 2025 have been fully processed and cleared to the original source of payment," the DGCA said in a statement.

The aviation regulator had told IndiGo that passengers hit by the imbroglio were entitled to compensation under Civil Aviation Requirement norms. IndiGo had informed the DGCA about introducing a one-time compensation offering additional vouchers worth ₹5,000 to ₹10,000 in what it called a "gesture of care".

Passengers whose flights were cancelled or delayed by more than three hours between December 3 and December 5 are eligible for compensation.

Many flyers took to social media to vent their frustration about the refund and compensation process, with several complaining of being denied the benefit despite their flights being cancelled during the period in question.

"Dear DGCA and team, all flight of 5th Dec from Delhi were cancelled. Why all flights are not covered here? My flight of 5th Dec was cancelled and not visible in impacted flights list here (sic)," an X user posted.

"The list shared by IndiGo does not have quite a few flights that were cancelled. It is difficult to understand why this is the case. They cancelled flights after the actual time of departure, yet, there is no mention (sic)," another user wrote on X.

Some termed the compen-



Passengers wait outside the IndiGo ticket counter at Mumbai airport's Terminal-1 on December 5 after several flights were cancelled. (Reuters)

sation an eyewash. "IndiGo6E I had applied for the gesture program but haven't received any confirmation so far!! Had submitted all details requested but no response! DGCAIndia is this an eye-wash as airlines isn't responding or delivering upon their promise (sic)," a social media user posted.

Asked about the complaints raised on social media, an IndiGo official told *The Telegraph* that the airline's customer care executives were dealing with passenger grievances.

Chaos onboard

A Krabi-bound IndiGo flight from Mumbai was delayed for more than three hours, leading to altercations between the crew members and the passengers.

The airline cited multiple reasons behind the delay in takeoff and said two passengers behaved "inappropriately" during the wait time and were declared "unruly". Flyers who had boarded the flight alleged that there was no communication to them from the airline.

"IndiGo flight 6E 1085 to Krabi was initially delayed from Mumbai due to a combination of reasons, including late arrival of incoming aircraft, air traffic congestion and crew exceeding their duty time limitations," IndiGo said in the statement.

DGCA slaps IndiGo with fine of ₹22cr for flight disruptions

Airline Also Has To Submit Bank Guarantee Of ₹50Cr

Saurabh Sinha
@timesofindia.com

New Delhi: The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has slapped IndiGo with the steepest fine ever for an Indian carrier — Rs 22.2 crore — for its massive flight disruptions last month.

Additionally, the airline has to submit a bank guarantee of Rs 50 crore whose release is tied to implementing, among other things, the more humane flight duty norms for pilots aimed at enhancing flight safety. The regulator has warned senior airline officials,

WHY THE PENALTY?

- Over-optimisation of operations, **inadequate regulatory preparedness**
- Deficiencies in system software support
- **Shortcomings in mgmt structure** & operational control
- **Inability** to identify planning deficiencies, **maintain sufficient operational buffer**, implement revised flight duty rules
- **Overriding focus on maximising use of crew, aircraft**, network resources

als, including the CEO & COO. The senior VP of operation control centre has to be removed from his position.

➤ DGCA sought removal, P 18

Remove Sr VP, ops control centre, DGCA tells IndiGo

➤ Continued from P1

The senior VP of operation control centre has to be removed from his position and not given any accountable position in the future. The aviation ministry has ordered "an internal inquiry to identify and implement systemic improvements within DGCA".

The regulator late on Saturday night released key findings of the report by its four-member panel that probed IndiGo schedule collapse last month. The airline's unpreparedness and consequent inability to implement DGCA's new flight duty time limitation (FDTL) for pilots has cost it dear. Each day's exemption given for its Airbus A320 family pilots to ensure the airline was able to start resuming flights starting the second week of Dec is costing it Rs 30 lakh. This works out to Rs 20.4 crore for 68 days between Dec 5, 2025, & Feb 10, 2026.

The airline has been fined one-time Rs 30 lakh each on six more counts, which add up the fine to Rs 22.2 crore. The six failures include failure to comply with new FDTL rules, rest periods, "inadequate buffer margins in roster planning... failure to strike balance between commercial imperatives and crew members' ability to work effectively and failure of account-

able management to ensure overall functioning, financing, and conduct of operations to DGCA standards."

Between Dec 3 and 5, 2,507 IndiGo flights were cancelled and 1,852 were delayed that left over 3 lakh passengers stranded at airports across the airline's network. Flights had resumed gradually over the next week or so.

What caused the crisis:

"Over-optimisation of operations, inadequate regulatory preparedness along with deficiencies in system software support and shortcomings in management structure & operational control on the IndiGo", have been identified as the "primary causes for the disruption" by the DGCA probe panel. "The airline's management failed to adequately identify planning deficiencies, maintain sufficient operational buffer, and effectively implement the revised FDTL provisions," the report says.

Action against IndiGo:

Apart from fines, the airline's CEO has been cautioned "for inadequate overall oversight of flight ops and crisis management." Accountable manager & COO, Isidre Porqueras, has been warned for "failure to assess impact of winter schedule 2025 and revised FDTL leading to widespread disruptions." Senior VP (ops con-

trol centre) has been asked to be relieved from the post and not be given any accountable position in future. Warnings have been issued to flight ops and crew resource planning "for operational, supervisory, manpower planning and roster management lapses."

Way ahead:

DGCA has asked IndiGo to take appropriate action against any other personnel identified through its inquiry and submit a compliance report regarding the same. Sources say IndiGo has been made aware of the lapses of its senior officials, especially COO, and now the airline is expected to take action against them. "The findings underscore the need for operational planning, and effective management oversight to ensure sustainable operations and passenger safety & convenience," report says.

IndiGo statement:

Confirming receipt of DGCA ruling, airline said it is "committed to taking full cognisance of the orders and will, in a thoughtful and timely manner, take appropriate measures... an in-depth review of the robustness and resilience of the internal processes at IndiGo (is) underway to ensure that the airline emerges stronger out of these events in its otherwise pristine record of 19 plus years of operations".

NORTH CENTRAL RAILWAY
CORRIGENDUM No.-1
1st Corrigendum to Tender Notice No. - CEN00AGC0326 dated 08.01.2026.
Following modification in above tender notice is made in tender No. CEN00AGC0326 dated 08.01.2026.

Field Name	Existing Value	Modified Value
Validity of Offer (Days)	30 days	60 days
New Documents	Not exist	Functional Specification for Rubricated Surface at Level Crossings

For more details, please visit <https://www.nrcr.india.gov.in/> 59/26 (A)
f North central railways | @NCRWCI

DGCA slaps ₹22.2-cr fine on IndiGo over Dec flight mess

SHEKHAR SINGH

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, JANUARY 17

The aviation regulator, DGCA, has imposed a penalty of Rs 22.20 crore on IndiGo and ordered the airline to furnish a Rs 50-crore bank guarantee for nationwide flight disruptions in December 2025 that stranded over three lakh passengers.

The action comes after a government-directed inquiry found that systemic failures, weak oversight and aggressive over-optimisation of crew and aircraft led to the chaos.

The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) had constituted a four-member committee on the directions of the Ministry of Civil Aviation to examine the large-scale delays and cancellations between December 3 and 5 last year, during which IndiGo cancelled 2,507 flights and delayed 1,852 flights across the country.

The committee's findings, now accepted by the DGCA, concluded that the primary causes for the disruption were "over-optimisation of operations, inadequate regulatory preparedness along with deficiencies in system software support and shortcomings in management structure and operational control on the part of IndiGo".

The inquiry observed that

DGCA slaps ₹22.2-crore fine on IndiGo...

warned for failing to assess the operational impact of the Winter Schedule 2025 and the revised FDTL CAR. The senior vice-president of the Operations Control Centre has been warned and directed to be relieved of operational responsibilities and barred from holding any accountable position.

According to DGCA officials, warnings have also been issued to the Deputy Head of Flight Operations, AVP of Crew Resource Planning and the Director of Flight Operations. IndiGo has been directed to take action against any other personnel identified through its internal inquiry and submit a compliance report.

The DGCA has imposed a



FILE PHOTO

TOLD TO FURNISH ₹50-CR BANK GUARANTEE

- DGCA has directed the airline to furnish ₹50-crore bank guarantee to ensure compliance with its directives and long-term reforms
- It has cautioned InterGlobe Aviation CEO Pieter Elbers for inadequate oversight of flight operations and crisis management
- The aviation regulator has directed the airline to act against erring officials identified in internal probe and submit a compliance report

the airline's management failed to identify planning deficiencies, did not maintain sufficient operational buffer and was unable to effectively implement the revised flight duty time limitation (FDTL) provisions.

It noted that IndiGo's "overriding focus on maximising utilisation of crew, aircraft and network resources significantly reduced roster buffer margins", which compromised operational resilience and resulted in large-scale delays and cancellations. Crewrosters

were stretched to maximise duty periods and relied heavily on dead-heading, tail swaps and extended duty patterns, weakening the airline's ability to recover from disruptions.

Based on these findings, the DGCA has initiated enforcement action against senior officials of InterGlobe Aviation. CEO Pieter Elbers has been cautioned for inadequate oversight of flight operations and crisis management. The accountable manager and COO has been

CONTINUED ON PAGE 7

one-time penalty of Rs 1.80 crore on IndiGo for six separate violations of regulatory provisions, including failure to implement an effective FDTL scheme, failure to balance commercial imperatives with crew fatigue, improper delegation of operational control and failure of accountable management to ensure DGCA-compliant operations.

In addition, the regulator imposed a further penalty of Rs 20.40 crore for 68 days of continued non-compliance with the revised FDTL CAR provisions from December 5, 2025, to February 10, 2026, bringing the total penalty to Rs 22.20 crore.

To ensure long-term reforms, IndiGo has been ordered to pledge a Rs 50

crore bank guarantee under the IndiGo Systemic Reform Assurance Scheme. The phased release of this guarantee will be tied to verifiable reforms in leadership and governance, manpower planning and fatigue-risk management, digital systems and operational resilience, and sustained board-level oversight.

The DGCA has acknowledged that IndiGo restored its operations to normal levels swiftly and ensured timely refunds and compensation for affected passengers. "Further, on the directions of MoCA, an internal inquiry is being undertaken to identify and implement systemic improvements within the DGCA," said the official.